RNI No. MPHIN/2015/64451 डाक पंजीयन क्र. MP/IDC/1525/2019-2021 IPT डाक द्वारा प्रेषण प्रति शुक्रवार indianplasttimes@gmail.com
www.Indianplasttimes.in

इंडियन प्लास्ट टाइम्स

■ INDORE ■ 08 JULY TO 14 JULY 2020 ■ प्रति बुधवार ■ वर्ष 05 ■ अंक 46 ■ पृष्ठ 8 ■ कीमत 5 रु.

Inside News

बीपीसीएल को अब तक 62 पेटेंट मिले, 68 नवाचारों को मंजूरी का इंतजार Page 2

TDS से जुड़े नियम बदले, जरा सी गलती जेब पर पड़ सकती है भारी Page 3

नहीं खरीदना पड़ेगा चीनी सामान, राखी से लेकर दिवाली तक सभी त्योहार होंगे भारतीय Page 4

editoria!

सुधार के संकेत

करीब 20 दिनों के भारी तनाव के बाद चीन की मनमानी में आई नरमी खुशी का मौका न सही, एक बेहतर संकेत तो है ही। गलवान में विवादित जगह से अपना अस्थाई तंबू लेकर करीब एक किलोमीटर या ज्यादा पीछे जाने की चीनी पहल एक ऐसा समाचार है, जिसका इंतजार भारत ही नहीं, दुनिया को था। यह स्वीकार करने में कोई हर्ज नहीं कि भारत की ओर से डाले गए चौतरफा दबाव की वजह से चीन ने कुछ नरमी दिखाई है, पर इस एक नरमी की वजह से अभिभूत नहीं होना चाहिए। समाधान के लिए अनेक दौर की सैन्य स्तरीय वार्ता के बाद हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को भी आगे आना पड़ा है। अब चीन की ओर से कोशिश दिख रही है कि हालात को और बिगड़ने से रोका जाए। हालांकि अभी विवाद का समाधान नहीं हुआ है और चीन की यह कार्यवाही दुनिया को दिखाने के लिए भी हो सकती है। अब तनाव वाली जगह से वह पीछे जाएगा और उसे ऐसा करना ही चाहिए, क्योंकि भारत अब इस स्थिति में नहीं है कि किसी देश की नाजायज मनमानी पचा जाए। भारत सरकार ने एकाधिक कदम चीन को यह संकेत देने के लिए उठाए थे कि अगर वह पीछे नहीं हटा, तो मजबूरन उसके खिलाफ फैसलों का सिलसिला चल पड़ेगा। भारत से मिले शुरुआती संकेतों को चीन यदि समझ गया है, तो यह जरूर खुशखबरी हो सकती है। विशेषज्ञ मानते हैं कि चीन केवल अपने आर्थिक हितों को लेकर चिंतित है। उसे 1962 से पहले या उसके बाद भी भारत की ज्यादा परवाह कभी नहीं रही है और वह अपनी भारत संबंधी नीतियों या मंशा का इजहार पाकिस्तान के साथ दोस्ती निभाते हुए सतत करता रहा है। भारत में जब 59 एप पर पाबंदी लगी, जब अनेक ठेके रद्द हो गए, तब शायद चीन जागा है, हालांकि इसमें रूस की भी भूमिका बताई जा रही है। बहरहाल, भारत को अपने रुख का इजहार आर्थिक मोर्चे पर संकेत देते हुए करते रहना चाहिए। वह भारत में विभिन्न उत्पादों का सबसे बड़ा निर्यातक है। भारत के साथ उसका कारोबार उसके लिए बहुत फायदेमंद रहा है। चीन के लिए हमारे निर्यात की तुलना में भारत के लिए चीन का जो निर्यात रहा है, उसमें चीन को 60 अरब डॉलर से ज्यादा की बढ़त हासिल है। भारत में चीनी निर्यात में स्मार्टफोन, विद्युत उपकरण, पावर प्लांट उपकरण, उर्वरक, ऑटो पार्ट्स, तैयार स्टील उत्पाद, बिजली संयंत्रों के सामान, दूरसंचार उपकरण, मेट्रो रेल कोच, दवा सामग्री, रसायन, प्लास्टिक, इंजीनियरिंग के सामान शामिल हैं। भारत से संबंध बिगड़ने से चीन में 20 से ज्यादा उद्योगों पर सीधी चोट पडेगी। मंदी से जूझ रहा चीन वाम-प्रेरित मनमानी के नशे के बावजूद अपने आर्थिक हित की चिंता जरूर करेगा। अब गलवान से यदि वह स्थाई तौर पर पीछे हटा है, तो भी हमें अपनी स्वाभाविक उदारता दिखाने की जल्दी नहीं करनी चाहिए। भूटान की जमीन पर भी उसका दावा चर्चा में है। चीन की नजर भूटान के सकटेंग इलाके पर है, जहां भूटान वन्यजीव अभयारण्य बनाना चाहता है। चीन ने तीसरे पक्ष (भारत) को भी चेतावनी देते हुए इस क्षेत्र को विवादित बताया है। सचेत रहना चाहिए, कोई साम्राज्यवादी पड़ोसी किसी इलाके को विवादित करार दे, तो इसका मतलब यह कतई नहीं कि हम या भूटान अपने-अपने इलाके को छोड़ दें। यह निर्णायक समय है। हमारी सुविचारित और संयमित दृढ़ता ही हमारा मार्ग प्रशस्त करेगी

पेट्रोल, डीजल के दाम स्थिर सीमित दायरे में है कच्चा तेल

नई दिल्ली। एजेंसी

पेट्रोल और डीजल के दाम में बुधवार को कोई बदलाव नहीं हुआ। एक दिन पहले तेल कंपनियों ने डीजल के दाम में बढ़ोतरी की थी। पेट्रोल के दाम लगातार नौवें दिन स्थिर हैं। उधर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का भाव बीते कुछ सप्ताह से सीमित दायरे में बना हुआ है। इंडियन ऑयल की वेबसाइट के अनुसार, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में डीजल की कीमत बुधवार को बिना किसी बदलाव के क्रमशः 80.78 रुपये, 75.89 रुपये, 79.05 रुपये और 77.91 रुपये प्रति लीटर बनी रही। वहीं पेट्रोल का भाव चारों महानगरों में लगातार नौवें दिन बिना किसी बदलाव के क्रमशः 80.43 रुपये, 82.10 रुपये, 87.19 रुपये और 83.63 रुपये प्रति लीटर बना हुआ है। तेल विपणन कंपनियों ने मंगलवार को दिल्ली और कोलकाता में डीजल के दाम में 25 पैसे जबकि मुंबई में 22 पैसे और चेन्नई में 19 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की थी, जोकि इस महीने की डीजल के दाम में पहली बढ़ोतरी है। बता दें कि काफी लंबे अंतराल के बाद तेल विपणन कंपनियों ने सात जून से पेट्रोल और डीजल के दाम में वृद्धि का सिलसिला शुरू किया जिसके बाद राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में डीजल 11.39 रुपये लीटर महंगा हो गया है जबकि पेट्रोल की कीमत 9.17 रुपये प्रति लीटर बढ़ गई है।

दिल्ली में पेट्रोल के मुकाबले डीजल 35 पैसे प्रति लीटर उंचे भाव पर मिल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय वायदा बाजार इंटरकांटिनेंटल एक्सचेंज (आईसीई) पर बेंचमार्क कच्चा तेल ब्रेंट क्रूड के सितंबर वायदा अनुबंध में बुधवार को पिछले सत्र से 0.26 फीसदी की कमजोरी के साथ 42.97 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार चल रहा था। जबकि इससे पहले ब्रेंट का भाव 43.18 डॉलर प्रति बैरल से 42.76 डॉलर प्रति बैरल के बीच रहा। ब्रेंट क्रूड का भाव बीते एक महीने से 37.01 डॉलर से लेकर 43.93 डॉलर प्रति बैरल के बीच रहा है। वहीं, न्यूयार्क मर्केंटाइल एक्सचेंज (नायमैक्स) पर अमेरिकी लाइट क्रूड वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (डब्ल्यूटीआई) के अगस्त वायदा अनुबंध में पिछले सत्र से 0.34 फीसदी की कमजोरी के साथ 40.48 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार चल रहा था।

तीन प्लास्टिक उत्पाद बैन लिस्ट से किए बाहर

चंडीगढ़। एजेंसी

एक बार इस्तेमाल किए जाने वाले प्लास्टिक उत्पादों को प्रशासन ने बैन किया हुआ है लेकिन अब अपने आदेशों में कुछ बदलाव करते हुए तीन प्लास्टिक उत्पादों को इस लिस्ट से बाहर किया गया है। यूटी प्रशासन ने बैन किए प्लास्टिक उत्पादों में से 500 एमएल की क्षमता से कम वाले प्लास्टिक रिफिल पाउच, टेट्रा पैक के साथ मिलने वाले स्ट्रॉ और खाने की पैकिंग में इस्तेमाल किए जाने वाले मल्टीलेयर्ड पैकेजिंग को बैन आइटम्स की सूची में से फिलहाल के लिए बाहर कर दिया है। चंडीगढ़ प्रशासन ने जनवरी 2020 में सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया था और इसके इस्तेमाल पर जुर्माने का प्रावधान किया था। प्रशासन ने आदेश जारी करते हुए सभी प्रोडक्ट उत्पादों के नाम सहित उन पर प्रतिबंध प्रतिबंध लगाया था।

साथ ही प्लास्टिक के इन उत्पादों का उत्पादन करने वाली कंपनियों को 28 मार्च 2020 तक का समय दिया था, ताकि वह इन प्लास्टिक उत्पादों की जगह इनके अन्य विकल्पों की तलाश कर सकें। मार्च महीने में केंद्र सरकार की तरफ से लॉकडाउन लगा दिया गया, जिसकी वजह से इन प्लास्टिक उत्पादों का निर्माण करने वाली कंपनियां इनके विकल्प को नहीं तलाश पाईं। इसी कारण कंपनियों की तरफ से तारीख को आगे बढ़ाने की मांग की गई थी।

अन्य उत्पाद पहले की तरह ही रहेंगे बैन

प्रशासन की तरफ से स्पष्ट किया गया है कि तीनों उत्पादों को बनाने वाली कंपनियां ही इनके निपटान की जिम्मेदारी उठाएंगी। इसी शर्त पर इन्हें बैन की सूची से बाहर किया गया है। प्रशासन के आदेश के अनुसार बाकी उत्पाद पहले की तरह ही बैन रहेंगे। इनमें थर्माकोल, खाना पैक करने वाले प्लास्टिक के पाउच, पानी के सील ग्लास, सिंगल रेजर, एक बार इस्तेमाल किए जाने वाले पेन, सजावट के तौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले थर्माकोल सहित कई प्लास्टिक आइटम्स बैन रहेंगे। एनजीटी के आदेश के अनुसार कोई भी इनका उपयोग करते हुए पाया जाता है तो उस पर जुर्माने का प्रावधान है।

कमजोर मांग से कच्चातेल वायदा कीमतों में गिरावट

नयी दिल्ली। कमजोर मांग के कारण कारोबारियों ने अपने सौदों के आकार को कम किया जिससे वायदा कारोबार में बुधवार को कच्चातेल की कीमत 0.56 प्रतिशत की गिरावट के साथ 3,046 रुपये प्रति बैरल रह गई।

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में कच्चातेल के जुलाई माह में डिलीवरी वाले अनुबंध की कीमत 17 रुपये अथवा 0.56 प्रतिशत की गिरावट के साथ 3,046 रुपये प्रति बैरल रह गई जिसमें 5,109 लॉट के लिए कारोबार हुआ। कच्चातेल के अगस्त माह में डिलीवरी वाले अनुबंध की कीमत 24 रुपये अथवा 0.78 प्रतिशत की गिरावट के साथ 3,061 रुपये प्रति बैरल रह गई जिसमें 140 लॉट के लिए कारोबार हुआ। वैश्विक स्तर पर न्यूयॉर्क में वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट कच्चातेल की कीमत 0.02 प्रतिशत की गिरावट के साथ 40.61 डॉलर प्रति बैरल रह गई, जबकि ब्रेंट क्रूड की कीमत 0.19 प्रतिशत की तेजी के साथ 43.16 डॉलर प्रति बैरल हो गई।

कैट ने किया जूम का बहिष्कार, जियोमीट को अपनाया

नयी दिल्ली। एजेंसी

व्यापारियों के संगठन कनफेडेरशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने चीनी वस्तुओं के बहिष्कार के अपने राष्ट्रीय अभियान के तहत जूम ऐप का बहिष्कार करने का फैसला किया है। अब व्यापारियों से संवाद के लिए कैट रिलायंस की 'जियोमीट' ऐप का इस्तेमाल करेगा। कैट ने देश भर के व्यापारियों और सभी राज्यों में फैले व्यापारी संगठनों को यह सलाह दी है की वे अपने संवाद मंच के रूप में अब जूम का उपयोग न करें। कैट के महासचिव प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि हमारी प्रौद्योगिकी टीम अन्य ऐप का भी आकलन कर रही है। उन्होंने कहा कि यह निर्णय जूम के बारे में देशभर के व्यापारी नेताओं से प्राप्त आपत्तियों एवं सुझावों को ध्यान में रख कर लिया है। कैट ने कहा कि उसने यह कदम अपने 'भारतीय सामान-हमारा अभिमान' को सशक्त बनाने के लिए उठाया है। कैट ने कहा कि जूम हालांकि अमेरिकी ऐप है, किन्तु प्राप्त जानकारी के अनुसार उसका काफी डाटा चीन के जरिये जाता है और जूम के कुछ सर्वर चीन में भी हैं जिसकी वजह से डाटा के लीक होने का खतरा बना रहता है। इस आशंका को भी खारिज नहीं किया जाता की इसका दुरुपयोग भारत के हितों के खिलाफ भी सो सकता है।

रिलायंस की विमानन ईंधन स्टेशनों की संख्या 50 फीसदी बढ़ाने की योजना

नयी दिल्ली। अरबपति कारोबारी मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल) की योजना अपने विमानन ईंधन डिपो की संख्या में 50 प्रतिशत बढ़ोतरी करने की है। इस कारोबार का बड़ा हिस्सा अभी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के पास है और आरआईएल इसमें अधिक बाजार हिस्सेदारी पाना चाहती है। आरआईएल ने अपनी ताजा वार्षिक रिपोर्ट में कहा कि विमानन क्षेत्र में पिछले 52 महीनों में लगातार हासिल की गई दो अंकों की वृद्धि कोरोना वायरस महामारी के चलते इस समय भले ही रुक गयी हो , लेकिन भारत अगले पांच वर्षों तक सबसे तेजी से बढ़ने वाले विमानन बाजारों में बना रहेगा। किसी एक स्थान (जामनगर-गुजरात) पर दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी का संचालन करने वाली आरआईएल ने हवाई अड्डों पर विमानों में ईंधन भरने के कारोबार में अपनी मौजूदगी बढ़ाने की योजना बनाई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में फरवरी में भी हवाई यातायात नौ प्रतिशत बढ़ा। कोविड-19 महामारी के बाद भी मार्च में भारत सबसे बड़ा अप्रभावित बाजार था। हालांकि इसके बाद लॉकडाउन से भारतीय विमानन क्षेत्र भी प्रभावित हुआ। वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार इस दौरान आरआईएल ने घरेलू बाजार में अपनी हिस्सेदारी में सुधार किया। आरआईएल ने कहा कि वित्त वर्ष 2019-20 के अंत तक आरआईएल अपने नेटवर्क 30 स्थानों से बढ़ाकर 45 स्थानों तक कर सकती है और भारतीय विमानन बाजार में वृद्धि के अवसरों का लाभ उठाने के लिए अच्छी तरह से तैयार है। भारत में इस समय 256 विमानन ईंधन स्टेशन हैं, जिनमें से सार्वजनिक क्षेत्र की इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के पास सबसे अधिक 119 स्टेशन हैं। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के पास 61 और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के पास बाकी 44 हैं। पेट्रोलियम मंत्रालय के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार आरआईएल 31 स्टेशनों के साथ निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी विमानन ईंधन की खुदरा विक्रेता है।

बीपीसीएल को अब तक 62 पेटेंट मिले, 68 नवाचारों को मंजूरी का इंतजार

मुंबई। आईपीटी नेटवर्क

भारत पेट्रोलियम के कॉरपोरेट शोध एवं विकास केंद्र (सीआरडीसी) को 19 साल पहले उसके गठन से अब तक 62 पेटेंट मिले हैं और 68 को मंजूरी का इंतजार है। सीआरडीसी के कार्यकारी निदेशक और प्रमुख संजय भार्गव ने फोन पर नई दिल्ली से बताया कि कुल पेटेंट नवाचारों में लगभग 20 का पहले ही व्यावसायीकरण किया जा चुका है और इनका बीपीसीएल के विभिन्न संयंत्रों में इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगले एक महीने के भीतर पांच-छह पेटेंट दाखिल किए जाएंगे। भार्गव ने कहा कि केंद्र ने 80-100 करोड़ रुपये के वार्षिक बजट के साथ 141 शोध लेख प्रकाशित किए हैं और इसके नवाचारों का पांच पुस्तकों में उल्लेख किया गया है। सीआरडीसी को वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग की मान्यता प्राप्त है और इसकी स्थापना विचारों को नवाचार में बदलने के लिए की गई थी। संस्था के प्रमुख पेटेंट नवाचारों में एक बीपीमार्क है, जो कच्चे तेल की परख करने वाला एक उन्नत उपकरण है और इससे समय की बहुत बचत होती है।

Bharat Petroleum

सरकार की 194 प्रकाश स्तंभ केन्द्रों को प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की योजना

नयी दिल्ली। एजेंसी

पोत परिवहन मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि उसने करीब 194 मौजूदा प्रकाश स्तंभों (लाइटहाउस) को प्रमुख पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने की योजना बनायी है। मंत्रालय के अनुसार साथ ही उन प्रकाश स्तंभों को चिन्हित किया जाएगा जो 100 साल से अधिक पुराने हैं।पोत परिवहन मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि केंद्रीय पोत परिवहन मंत्री मनसुख मांडविया ने मौजूदा करीब 194 प्रकाश स्तंभों के विकास और उसे प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिये उच्च स्तरीय बैठक की है। मांडविया ने कहा कि इस कदम का मकसद प्रकाश स्तंभ और उसके आसपास के क्षेत्रों में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देना तथा लोगों को इनसे जुड़े समृद्ध इतिहास के बारे में जानकारी उपलब्ध कराना है। मंत्रालय के अधिकारियों ने प्रकाश स्तंभ को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने के लिये विस्तृत कार्य योजना तैयार की है। उनसे उन प्रकाश स्तंभों को चिन्हित करने को कहा गया है, जो 100 साल से अधिक पुराने हैं। बयान के अनुसार मंत्री ने प्रकाश स्तंभ के इतिहास और उसके काम करने के तरीकों के बारे में जानकारी देने के लिये संग्रहालय बनाने पर भी जोर दिया। बयान के अनुसार मंत्री ने गुजरात के गोपनाथ, द्वारका और वेरावल प्रकाश स्तंभों को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किये जाने के कार्यों में प्रगति का जायजा भी लिया।उन्होंने अधिकारियों को परियोजना पर यथाशीघ्र विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने को कहा है।बैठक में पोत परिवहन सचिव, लाइटहाउस और लाइटशिप महानिदेशक एवं अन्य संबद्ध पक्ष शामिल हुए।

शुरुआती कारोबार में डॉलर के मुकाबले रुपया हुआ कमजोर, 5 पैसे गिरकर 74.98 पर

मुंबई। एजेंसी

अंतर बैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में बुधवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया शुरुआती कारोबार में 5 पैसे गिरकर 74.98 रुपए प्रति डॉलर पर पहुंच गया। अमेरिकी मुद्रा में मजबूती और घरेलू बाजार में हल्की तेजी को देखते हुए रुपया नरम रहा। विदेशी मुद्रा कारोबारियों का कहना है कि कच्चे तेल के स्थिर चल रहे दाम और विदेशी मुद्रा प्रवाह जारी रहने से रुपए को समर्थन मिला है लेकिन दूसरी तरफ मजबूत होते डॉलर और कोविड-19 संक्रमण के बढ़ते मामलों से रुपया कमजोर पड़ा है। अंतर बैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में कारोबार की शुरुआत में रुपया 74.88 रुपए प्रति डॉलर के दाम पर सकारात्मक रुख में खुला लेकिन जल्द ही गिरकर 74.98 रुपए प्रति डॉलर पर पहुंच गया। पिछले दिन के मुकाबले यह 5 पैसे नीचे रहा। मंगलवार को रुपया 74.93 रुपए प्रति डॉलर पर बंद हुआ था।

रेलवे का मिशन शीघ्र, 100 किमी की रफ्तार से दौड़ी मालगाड़ी

नई दिल्ली। एजेंसी

भारतीय रेलवे यात्री गाड़ियों के साथ-साथ मालगाड़ियों की रफ्तार बढ़ाने पर भी काम कर रहा है। इस समय पटरियों पर बहुत कम ट्रेनें चल रही हैं और रेलवे इस मौके पूरा फायदा उठा रहा है। लॉकडाउन के दौरान रेलवे ने सुरक्षा, रखरखाव और मरम्मत से जुड़ी 200 से ज्यादा पुरानी परियोजनाओं को पूरा किया। इसी क्रम में रेलवे 'मिशन शीघ्र' (Mission Sheeghra) के तहत लखनऊ डिवीजन में 100 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से मालगाड़ी (Freight Train) चलाने में सफल रहा है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने खुद ट्वीट कर मालगाड़ी के 100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चलने की जानकारी साझा की है। उन्होंने ट्वीट के साथ मालगाडी के स्पीडोमीटर का वीडियो भी शेयर किया है।

ट्रेनों ने समय पर पहुंचने रेकॉर्ड

यात्री हमेशा से ट्रेनों के लेट होने की शिकायत करते थे। लेकिन हाल में भारतीय रेल के इतिहास में पहली बार 100 फीसदी ट्रेनें अपने निर्धारित समय पर चलने और गंतव्य पर पहुंचने में सफल रही हैं। भारतीय रेलवे ने 1 जुलाई 2020 को 201 ट्रेनों का संचालन किया। ये सभी ट्रेनें तय समय पर चलीं और आखिरी स्टेशन तक तय समय पर ही पहुंच गईं। ऐसा कर भारतीय रेलवे ने पहली बार ट्रेन के टाइम पर चलने और पहुंचने के मामले में 100 फीसदी सफलता हासिल की है। रेलवे के इतिहास में पहली बार हुआ कि एक भी ट्रेन बिना देरी के गंतव्य स्टेशन तक पहुंची। हालांकि सामान्य स्थिति में देश में एक दिन में 11 हजार ट्रेनें चलती हैं। अब देखना होगा कि रेलवे का संचालन सामान्य होने के बाद यह रेकॉर्ड बरकरार रह पाता है या नहीं।

कोरोना काल में मालगाड़ी का जलवा

कोरोना काल में मालगाड़ी ने देशभर में जरूरी सामान की आपूर्ति में अहम भूमिका निभाई है। इस दौरान मालगाड़ी की औसत रफ्तार में सुधार पर भी काम किया गया है। रेल मंत्रालय ने हाल में बताया था कि 21 जून 2020 तक इन ट्रेनों की औसत रफ्तार पिछले साल के मुकाबले करीब दोगुनी हो गई है। मंत्रालय के मुताबिक, जून 2018 के दौरान इन ट्रेनों की औसत रफ्तार 23 किमी प्रति घंटा था, जो जून 2020 में करीब दोगुनी होकर 42 किमी प्रति घंटा हो गई है।

पटरियों पर दौड़ी सुपर एनाकोंडा

भारतीय रेलवे ने हाल में दो किमी लंबी ट्रेन 'सुपर एनाकोंडा' चलाकर नया रेकॉर्ड बनाया। यह पहला मौका था जब देश में इतनी लंबी ट्रेन पटरियों पर दौड़ाई गई। माल से लदी हुई 177 बोगियों वाली इस मालगाड़ी का पटरी पर दौड़ना रेलवे के लिए बड़ी उपलब्धि है। यह मालगाड़ी छत्तीसगढ़ से ओडिशा तक चलाई गई। सुपर एनाकोंडा ने 325 किमी की दूरी तय करने के दौरान 100 से अधिक दुर्गम ट्रैक को पार किया। इस दौरान सुपर एनाकोंडा की रफ्तार 50 किमी प्रति घंटा तक पहुंची, जो औसत से दोगुना है।

TDS से जुड़े नियम बदले, जरा सी गलती जेब पर पड़ सकती है भारी

नई दिल्ली। एजेंसी

आयकर विभाग (Income Tax Department) ने टीडीएस फॉर्म को व्यापक बनाने के लिये इसमें कुछ बदलाव किए हैं। इनमें कर की कटौती नहीं करने के कारणों की जानकारी देने को अनिवार्य बनाना भी शामिल है। बैंकों को नये फॉर्म में एक करोड़ रुपये से अधिक की नकदी निकासी पर 'स्रोत पर की गई कर की कटौती' (टीडीएस) की जानकारी भी देनी होगी। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने एक अधिसूचना के माध्यम से ई-वाणिज्य ऑपरेटरों, म्यूचुअल फंड और कारोबार न्यासों के द्वारा लाभांश वितरण, नकदी निकासी, पेशेवर शुल्क और ब्याज पर टीडीएस लगाने के लिये आयकर नियमों को संशोधित किया है। नांगिया एंड कंपनी एलएलपी के पार्टनर शैलेश कुमार ने कहा कि सरकार ने इस अधिसूचना के साथ फॉर्म 26 क्यू और 27 क्यू के प्रारूप को संशोधित किया है। फॉर्म 26 क्यू का उपयोग भारत में सरकार या कंपनियों द्वारा कर्मचारियों (भारतीय नागरिक) को वेतन के अलावा किये गये किसी भी अन्य भुगतान पर टीडीएस कटौती का तिमाही के आधार पर जानकारी देने में होता है। इसी तरह फॉर्म 27 क्यू का उपयोग अनिवासी भारतीयों को वेतन के अलावा किसी अन्य भुगतान पर टीडीएस कटौती और उसे जमा कराए जाने की जानकारी देने में होता है।

ज्यादा व्यापक है नया फॉर्म

कुमार ने कहा कि नए फॉर्म अधिक व्यापक हैं और भुगतान करने वालों को न केवल उन मामलों की सूचना देने की आवश्यकता होगी, जिनमें टीडीएस काटा जाता है, बल्कि जिन मामलों में टीडीएस नहीं काटा गया है, अब उनकी भी सूचना देनी होगी। सरकार ने नकदी में लेन-देन को हतोत्साहित करने के लिये 2019-20 के बजट एक वित्तीय वर्ष में एक बैंक खाते से एक करोड़ रुपये से अधिक की नकद निकासी पर दो प्रतिशत का टीडीएस लगाया था।

कोरोना से पस्त इकनॉमी को गांवों से मिलेगी रिकवरी की डोज!

नांगिया ने कहा कि नया टीडीएस फॉर्म पहले की तुलना में व्यापक है। इसमें जिस रकम पर टीडीएस कटा है, उसके बारे में जानकारी तो देनी ही होगी। लेकिन, इसके अलावा अब टैक्सपेयर्स को वो रकम भी डिसक्लोज करना अनिवार्य होगा, जिसपर किसी वजह से टीडीएस नहीं कटा है। कम दर पर टीडीएस कटने या टीडीएस बिल्कुल ने कटने की विभिन्न स्थिति के लिए अलग-अलग कोड उपलब्ध कराया गया है। नियम 31A में संशोधन के बाद यह अनिवार्य हो गया है कि करदाता उस रकम के बारे में भी जानकारी दे, जिसका उसने भुगतान किया है लेकिन इस पर टैक्स नहीं कटा है या कम दर पर टैक्स कटा है।

लॉकडाउन में जीएसटी कलेक्शन घटकर आधा

नई दिल्ली। एजेंसी

लॉकडाउन का जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) पर बहुत विपरीत प्रभाव पड़ा है। अप्रैल, मई, जून तीन महीनों में इस बार जीएसटी कलेक्शन पिछली बार की तुलना में आधा रह गया है। कोरोना को हराने के लिए पूरे देश में 25 मार्च को लॉकडाउन लगाया गया था। लॉकडाउन में घर से निकलने पर लगी पाबंदी के बाद सभी प्रकार के रोजगार ,व्यावसाय ठप हुए। इसका असर सरकार को मिलने वाले राजस्व पर पड़ा है। जीएसटी कलेक्शन पिछली वर्ष के मुकाबले 45 फीसदी कम हुआ है। वस्तु एवं सेवा कर से मिले आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2019 में अप्रैल,मई तथा जून महीने में 22 करोड़ रुपये का जीएसटी कलेक्शन हुआ था। इस बार जब दुकानों, प्रतिष्ठानों और उद्योग धंधों पर रोक लगी तो यह कलेक्शन घट कर 12.30 करोड़ रुपये रह गया। विभाग को मिला जीएसटी कलेक्शन पिछले वर्ष से 45 फीसदी कम है। अब पूरे देश में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है तो उम्मीद है कि उद्योग धंधे शुरू होने के साथ ही जीएसटी कलेक्शन भी बढेगा । इसके लिए विभाग ने जिम्मेदारी भी तय कर दी है।

कम्पोजिशन डीलरों के लिए बढ़ सकती है रिटर्न की तारीख

नई दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने मंगलवार को कहा कि माल एवं सेवा कर (जीएसटी) क्रियान्वयन समिति कम्पोजिशन योजना का डीलरों के लिए बीते 2019-20 के वार्षिक रिटर्न की तारीख बढ़ाने पर विचार कर रही है। सीबीआईसी ने ट्वीट किया, 'साझा पोर्टल पर उपलब्धता नहीं होने तथा 2019-20 के लिए फॉर्म जीएसटीआर-4 जमा कराने की तारीख बढ़ाने के बारे में ज्ञापन मिले हैं। जीएसटी क्रियान्वयन समिति इस पर विचार कर रही है।'

कम्पोजिशन डीलरों के लिए बीते वित्त वर्ष का जीएसटीआर-4 जमा कराने की तारीख तीन अप्रैल, 2020 को बढ़ाकर 15 जुलाई, 2020 की गई थी। एएमआरजी एंड एसोसिएट्स के वरिष्ठ भागीदार रजत मोहन ने कहा, 'जीएसटीएन अभी तक सुगमता से रिटर्न दाखिल करने की सुविधा नहीं उपलब्ध करा पाया है। ऐसे में इसकी तारीख आगे बढ़ाने जाने की संभावना है।'

कौन चुन सकता है कम्पोजिशन योजना का विकल्प

कोई भी करदाता जिसका कारोबार 1.5 करोड़ रुपये से कम है जीएसटी कम्पोजिशन योजना का विकल्प चुन सकता है। इस योजना के तहत विनिर्माताओं और व्यापारियों को एक प्रतिशत जीएसटी का भुगतान करना होता है। वहीं शराब उपलब्ध नहीं कराने वाले रेस्तरांओं को पांच प्रतिशत जीएसटी देना होता है।

खादी ने भी बनाया मास्क, ऑनलाइन बिक्री शुरू

नई दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

कोरोना संक्रमण से बचने के लिए मास्क को सबसे कारगर माना जा रहा है। इसके मद्देनजर खादी ने भी अब मास्क की ऑनलाइन बिक्री शुरू कर दी है। इससे देश के दूरदराज के लोग भी अब घर बैठे मास्क मंगा सकते हैं। खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) कॉटन और सिल्क के मास्क बेच रही है। कॉटन मास्क की कीमत 30 रुपये रखी गई है जबकि सिल्क के मास्क के लिए 100 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। ऑनलाइन मिनिमम 500 रुपये का खरीद ऑर्डर दिया जा सकता है। खादी के मास्क के लिए http://www.kviconline.gov.in/khadimask पर ऑर्डर दिया जा सकता है। खादी चार तरह के मास्क बेच रही है। इनमें ब्लैक पाइपिंग के साथ सफेद कॉटन मास्क, तिरंगे की पाइपिंग के साथ सफेद कॉटन मास्क, सॉलिड कलर में सिल्क मास्क और मल्टीपल कलर में प्रिंटेड सॉलिड मास्क शामिल है। केवीआईसी ऑर्डर करने के 5 दिन के भीतर मास्क की मुफ्त डिलीवरी करेगी। अभी केवल देश मी ही इन मास्क की ऑनलाइन बिक्री की जा सकती है।

आयकर विभाग ने बुनियादी ढांचा में निवेश से आय पर सरकारी संपत्ति कोष को कर छूट अधिसूचित किया

नयी दिल्ली। एजेंसी

आयकर विभाग ने सरकारी संपत्ति कोषों (एसडब्ल्यूएफ) और वैश्विक पेंशन कोषों की ओर से भारत के बुनियादी ढांचे में निवेश से प्राप्त पूंजी लाभ आय, ब्याज और लाभांश पर कर छूट की अधिसूचना जारी कर दी है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने छह जुलाई को अधिसूचना के जरिये वित्त अधिनियम 2020 के माध्यम से पेश आयकर कानून की धारा 10 (23 एफई) के तहत आयकर छूट के लिये 'बुनियादी ढांचे' में निवेश को भी शामिल कर दिया है। नांगिया एंडरसन एलएलपी के भागीदार अरविंद श्रीवत्सन ने कहा कि यह प्रावधान अबू धाबी निवेश प्राधिकरण, एसडब्ल्यूएफ और पेंशन कोष को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है ताकि वे भारत में अपनी प्रतिबद्धता या निवेश बढ़ा सके। उन्होंने कहा, "अधिसूचना के बाद इन निवेशकों द्वारा सीधे या वैकल्पिक निवेश कोष (एआईएफ) जैसे माध्यमों से निर्धारित 34 बुनियादी ढांचा क्षेत्रों में निवेश इस छूट के लिये पात्र होगा।" अधिसूचना एक अप्रैल 2021 से प्रभाव में आएगी और आकलन वर्ष 2021-21 और उसके बाद के आकलन वर्षों पर लागू होगी। एकेएम ग्लोबल टैक्स पार्टनर अमित महेश्वरी ने कहा कि "इससे वैश्विक सरकारी सम्पत्ति कोष भारत में दूरसंचार, ऊर्जा, अस्पताल और शीत गृह श्रृंखला जैसे विभिन्न बुनियादी ढांचों के विकास में लगी कंपनियों में निवेश के लिये आकर्षित होंगे।" वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2020-21 के बजट में इस छूट की घोषणा की थी।

नहीं खरीदना पड़ेगा चीनी सामान, राखी से लेकर दिवाली तक सभी त्योहार होंगे भारतीय

नई दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

कोरोना वायरस की वजह से देश भर में अभी भी लॉकडाउन का बंधन (Restrictions of Lock Down) पूरी तरह से हटा नहीं है। इसी बीच सीमा पर चीन से चल रहे विवाद के बीच देश भर में अगले महीने अगस्त से लेकर नवम्बर तक त्योहारी सीजन (Festival season) शुरू हो रहा है। ऐसी हालत में इस बार त्योहारों पर बाज़ारों में शायद वो गहमगहमी न दिखाई दे जो हर वर्ष दिखाई देती है। लेकिन इस बार ऐसी तैयारी हो रही है कि आपको बाजार में शत प्रतिशत भारतीय सामान ही दिखाई देगा। इस दौरान चीनी सामान पूरी तरह से बाजार से गायब होंगे। इसकी तैयारी छोटे कारोबारियों के संगठन ने की है।

3 अगस्त से शुरू हो रहा है त्योहारी मौसम

देश भर के करीब 7 करोड़ छोटे कारोबारियों के प्रतिनिधित्व का दावा करने वाले संगठन कंफेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (CAIT) ने दिल्ली सहित देश के सभी व्यापारी संगठनों को संदेश दिया है कि आगामी 3 अगस्त से शुरू हो रहे राखी के त्यौहार से लेकर 25 नवंबर, तुलसी विवाह तक, सभी त्योहारों में काम आने वाले सभी भारतीय सामानों को देश भर में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध कराया जाए। इससे किसी भी व्यक्ति को भारतीय सामान खरीदने में कोई समस्या न आये। इन तीन महीने के त्योहारी सीजन में राखी, जन्माष्टमी, गणेशोत्सव, नवरात्रि, दुर्गा पूजा, धनतेरस, दिवाली, भैया दूज, छठ एवं तुलसी विवाह आदि त्यौहार आएंगे। ऐसी तैयारी है कि हर त्योहार पर भारतीय सामान आसानी से प्राप्त हो।

कैट ने बनायी है व्यापक योजना

कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष बी सी भरतिया बताते हैं कि इस सम्बन्ध में कैट ने एक बहुत ही व्यापक योजना बनाई है। इस त्योहारी सीजन में आने वाले सभी त्योहारों पर उपयोग में आने वाली सभी वस्तुओं की एक सूची कैट तैयार कर रहा है जो 11 जुलाई तक पूरी हो जायेगी। कैट ने सभी प्रदेशों में काम कर रही राज्यस्तरीय टीम तथा अन्य प्रमुख व्यापारी संगठनों को सलाह दी है कि वे इन त्योहारों से सम्बंधित भारतीय सामान बनाने वाले निर्माता, कारीगर, लघु उद्यमी, कुम्हार, महिला उद्यमी, स्वरोजगारी उद्यमी, स्टार्टअप आदि से संपर्क स्थापित करें। साथ ही वह यह आंकड़ा तैयार करें कि उनके राज्य में कितनी मात्रा में यह सामान बनता है। दूसरी ओर उनके राज्य में उन सामानों की कितनी खपत होती है उसका भी डाटा एकत्र करें। इसके लिए कैट ने अंतिम तारीख 15 जुलाई तय की है।

मांग एवं आपूर्ति के बीच बनाया जाएगा तालमेल

भरतिया का कहना है कि यह डाटा कैट के दिल्ली स्थित केंद्रीय कार्यालय में आएगा जिसमें दोनों डाटा के आधार पर किस राज्य में कितना सामान बन रहा है और उस राज्य में उनकी खपत को छोड़कर बाकी बचा सामान किस राज्य में भेजा जाए जहाँ उसकी जरूरत है का एक बृहद डाटा तैयार होगा। इसके अनुरूप कैट देश भर में मांग और आपूर्ति के बीच एक तालमेल बैठा कर संबंधित व्यापारियों के लिए यह सुनिश्चित करेगा की देश में कहीं भी भारतीय सामान का अभाव न हो।

इन सामानों की किफायती दर पर होगी ढुलाई

कैट का कहना है कि इन सामानों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाने-ले जाने में (ट्रांसपोर्टेशन का सारा काम) देश के ट्रांसपोर्टरों के शीर्ष संगठन आल इंडिया ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन (All India Transport welfare Association) बेहद किफायती दरों पर करेगा। उन्हें पहले से ही बता दिया जाएगा कि फलाने राज्य के अमुक जगह से सामाना अमुक जगह लेकर लाना है। इसेक बाद इसकी व्यवस्था हो जाएगी।

महिला टीम की होगी महत्वपूर्ण भूमिका

भरतिया का कहना है कि इस भारतीय त्योहारी अभियान में कैट से संबंधित सभी राज्यों में महिला टीम की विशेष भूमिका होगी। कैट देश के सभी राज्यों में कार्यरत महिला संगठनों को प्रेरित करेगा कि त्योहार से सम्बंधित सामान महिलाओं के द्वारा ज्यादा से ज्यादा बनाया जाए।

माईलैन को भारत में रेमडिसिविर उतारने की अनुमति, प्रति शीशी कीमत 4,800 रुपये

नयी दिल्ली। एजेंसी

दवा कंपनी माईलैन एनवी को भारतीय दवा नियंत्रक से घरेलू बाजार में रेमडिसिविर उतारने और विनिर्माण की अनुमति मिल गयी है। कंपनी ने सोमवार को जानकारी दी कि इस दवा को कोविड-19 के सीमित और आपात इलाज में उपयोग करने की इजाजत होगी। कंपनी ने एक बयान में कहा कि इसकी प्रत्येक 100 मिलीग्राम शीशी की कीमत 4,800 रुपये होगी। यह इस माह से मरीजों के लिए बाजार में उपलब्ध होगी। कंपनी ने इसके उत्पादन के लिए घरेलू दवा कंपनी सिप्ला और हेटेरो के साथ गठजोड़ किया है। इन दोनों कंपनियों को इसके उत्पादन और विपणन के लिए दवा नियंत्रक डीसीजीआई से अनुमति मिल चुकी है। माईलैन ने कहा कि कंपनी की 100 मिलीग्राम रेमडिसिविर की शीशी को देश में कोविड-19 के सीमित इलाज में उपयोग की अनुमति मिली है। यह दवा अस्पताल में भर्ती उन वयस्कों और बच्चों पर उपयोग की जा सकेगी जिनमें कोरोना वायरस के गंभीर लक्षण हैं। बयान के मुताबिक भारत में इसे 'डीसरेम' ब्रांड नाम के तहत उतारा जाएगा। यह जुलाई में भारतीय बाजार में उपलब्ध हो जाएगी। इसकी कीमत 4,800 रुपये प्रति शीशी होगी जो इसके ब्रांडेड संस्करण से 80 प्रतिशत से भी अधिक सस्ती है। इसका ब्रांडेड संस्करण विकसित देशों की सरकार को उपलब्ध है।

अर्थव्यवस्था में सुधार के संकेत, जल्दी ही तेजी आएगी: अमिताभ कांत

नयी दिल्ली। एजेंसी

नीति आयोग के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) अमिताभ कांत ने मंगलवार को कहा कि कोविड-19 महामारी से प्रभावित अर्थव्यवस्था में सुधार के संकेत दिख रहे हैं और जल्दी ही इसमें तेजी आएगी। कोरोना वायरस महामारी और उसकी रोकथाम के लिये 'लॉकडाउन' से विभिन्न क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियां पूरी तरह ठप हो गयी थीं। अब धीरे-धीरे अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को खोला जा रहा है। सरकार ने अर्थव्यवस्था को गति देने के लिये प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा समेत नीतिगत कदम उठाये हैं। कांत ने 'फिक्की फ्रेम्स 2020' में कहा, ''मैं इस बात पर पूरा भरोसा करने वाला हूं कि भारत की स्थिति जल्द बेहतर होगी। हम अर्थव्यवस्था में सुधार के संकेत पहले ही देख रहे हैं। हम देख रहे हैं कि दैनिक उपयोग का सामान बनाने वाली कंपनियों जैसे क्षेत्र पटरी पर आ चुके हैं।'' आर्थिक गतिविधियों में नरमी से सरकार के राजस्व संग्रह पर असर पड़ा है। हालांकि धीरे-धीरे अर्थव्यवस्था को खोले जाने से आर्थिक गतिविधियां बढ़ रही हैं। जून में जीएसटी संग्रह 90,917 करोड़ रुपये रहा जो मई में 62,009 करोड़ रुपये तथा अप्रैल में 32,294 करोड़ रुपये था। ईंधन और बिजली मांग में भी अप्रैल और मई के मुकाबले तेजी देखी जा रही है।

कांत ने कहा कि महामारी एक बड़ी चुनौती है और यह केवल भारत के लिये ही नहीं बल्कि अमेरिका और यूरोपीय देशों समेत पूरी दुनिया के लिये है। उन्होंने कहा, ''हर संकट एक अवसर भी है। इसीलिए यह संकट भी सबकुछ गंवानों वालों और काफी कुछ हासिल करने वालों को देने जा रहा है। भारत यह निर्णय कर सकता है कि वह खोना चाहता है या फिर जीतना।'' उन्होंने कहा कि भारत को वृद्धि के 12-13 क्षेत्रों की पहचान करनी चाहिए जो कल के लिये विजेता बनने जा रहा है। उन्होंने इस संदर्भ में डेटा, कृत्रिम मेधा, जिनोमिक्स, मोबिलिटी जैसे क्षेत्रों को चिन्हित किया। कांत ने कहा, ''हमें 12-13 क्षेत्रों को पहचान करनी होगी जहां देश वैश्विक स्तर पर चैंपियन बन सकता है....।'' उन्होंने कहा कि ये क्षेत्र भारत को अगले 10-12 साल तक उच्च वृद्धि के रास्ते पर ले जाएंगे और बड़ी संख्या में रोजगार सृजित करेंगे। आत्मनिर्भर भारत के बारे में नीति आयोग के सीईओ ने कहा कि इसका आशय अलग-थलग होना और वैश्वीकरण के खिलाफ नहीं है। उन्होंने कहा, ''यह दुनिया से बेहतर चीजें लेने से जुड़ा है। इसका आशय वैट्टश्विक स्तर के उत्पाद बनाने से है। यह संरक्षणवाद नहीं है। यह भारतीय कंपनियों की वैश्विक स्तर के उत्पाद बनाने की क्षमता, भारतीय बाजार को हासिल करना तथा घरेलू बाजार की मजबूती का उपयोग कर वैट्टश्विक बाजारों में पैठ जमाने से संबद्ध है।'' उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिये आत्मनिर्भर भारत अभियान की घोषणा की है।

भारत एक 'महत्वपूर्ण डिजिटल शक्ति', डाटा 'संप्रभुता' से समझौता नहीं : प्रसाद

मुंबई। आईपीटी नेटवर्क

केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी एवं दूरसंचार मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने कहा है कि भारत आज एक 'महत्वपूर्ण डिजिटल ताकत' है और डाटा की संप्रभुता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। प्रसाद ने हीरानंदानी समूह की कंपनी योट्टा के 1,100 करोड़ रुपये के डाटा केंद्र के शुभारंभ के मौके पर कहा, ''मैं भारत को डाटा शोधन का केंद्र बनाना चाहता हू। इसमें डाटा को साफ-सुथरा करना और डाटा शोध शामिल है। ऐसे करते समय निजता से संबंधित चिंता को ध्यान रखा जाएगा।'' कुछ दिन पहले की सरकार ने 'संप्रभुता और सुरक्षा' चिंता के मद्देनजर चीन से संबंधित 59 ऐप पर रोक लगाई है। इसके एक दिन बाद प्रसाद ने इसे डिजिटल हमला करार दिया था। प्रसाद ने इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, ''हम देश के डाटा की संप्रभुता से कभी समझौता नहीं कर सकते। भारत एक महत्वपूर्ण डिजिटल शक्ति है, हमारे डाटा की संप्रभुता भी महत्वपूर्ण है। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि हम इससे किसी तरह का समझौता नहीं करेंगे।'' मंत्री ने कहा कि साइबर सुरक्षा एक महत्वपूर्ण पहलू है और हमें चीजों को लेकर सतर्क रहना होगा। प्रसाद ने कहा कि भारत को दुनिया के लिए एक डाटा शोधन या रिफाइनिंग केंद्र के रूप में आगे बढ़ाने की जरूरत है। इसके साथ ही हमें सॉफ्टवेयर के मोर्चे पर आगे बढ़ने और अपने उत्पाद बनाने की जरूरत है। उन्होंने कहा, ''डिजिटल भारत अभियान की सफलता के बाद भारत को अब डाटा को साफ-सुथरा और प्रसंस्कृत करने के लिए एक बड़ी डाटा रिफाइनरी बनने की जरूरत है। ऐसा करते समय डाटा की निजता की चिंता को ध्यान में रखा जाएगा।'' प्रसाद ने कहा कि दुनिया के 20 प्रतिशत इंटरनेट प्रयोगकर्ता भारत में है। लेकिन डाटा की कुल खपत में हमारा हिस्सा मात्र दो प्रतिशत है। उन्होंने कहा कि इसी के साथ प्रत्यक्ष लाभ अंतरण की बड़ी परियोजनाएं हैं, जिससे सरकार को पिछले कुछ साल के दौरान 1.70 लाख करोड़ रुपये की बचत हुई है। प्रत्येक तीन मिनट में तीन करोड़ आधार सत्यापन हो रहे हैं, जिसमें डाटा का सृजन हो रहा है। प्रसाद ने कहा कि भारत में बड़ी मात्रा में डाटा का सृजन हो रहा है, सवाल यह है कि हम उसका इस्तेमाल किस तरह से करें।

सेबी ने मानक परिचालन प्रक्रिया, अन्य नीतिगत दस्तावेज तैयार करने के लिये छह कंपनियों को छांटा

नयी दिल्ली। एजेंसी

पूंजी बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने बेहतर संचालन नीति और दस्तावेज तैयार करने और उन्हें अमल में लाने के लिये केपीएमजी, पीडब्ल्यूसी और अर्न्स्ट एण्ड यंग सहित छह कंपनियों को छांटा है। छह कंपनियों में तीन अन्य नाम हैं आरएसएम एस्टयूट कंसल्टिंग, बीडीओ इंडिया और एएनबी साल्यूसंश। पूंजी बाजार नियामक की योजना बेहतर नीतिगत दस्तावेज तैयार करने की है। जिसमें परिचालन की मानक प्रक्रिया और अन्य सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़े दस्तावेज भी होंगे। नियामक का मानना है कि उसके पास कुछ ऐसे नीतिगत दस्तावेज हो सकते हैं जिनमें इस क्षेत्र में अपनाये जाने वाले सबसे बेहतर उद्योग मानक और व्यवहार के मुताबिक कुछ बदलाव की जरूरत हो सकती है। इस योजना

के तहत ही नियामक ने फरवरी में एजेंसियों से रुचिपत्र आमंत्रित किये थे। ये रुचिपत्र सूचना प्रौद्योगिकी नीति की तैयारी, जोखिम आकलन और मानक परिचालन प्रक्रिया के दस्तावेज तैयार करने में विचार विमर्श के वास्ते मंगाये गये।

सेबी ने बीते दिनों जारी नोटिस में कहा है कि इसके बाद छह बोलीदाताओं का नाम छांटा गया है। नियामक ने रुचि पत्र आमंत्रित करते हुये कहा था कि संगठन के स्तर पर बखूबी तैयार की गई आईटी नीति, प्रक्रिया और नियमावली से परिचालन लागत कम होती है। इसके साथ ही कंप्यूटर, नेटवर्क, हार्डवेयर, साफ्टवेयर, सूचना सुरक्षा और आईटी वेंडर प्रबंधन के लिये स्पष्ट मानदंड इसमें तय होते हैं। जो भी एजेंसी का इस काम के लिये चुनाव होगा उसे सेबी के आईटी ढांचे को लेकर गहन जोखिम आकलन करने की जरूरत होगी। इसमें आने वाले समय में होने वाले जोखिम का भी आकलन करना होगा, संभावित जोखिम से होने वाले नुकसान और इस नुकसान को कम से कम करने जैसे उपायों के बारे में आकलन करना होगा। एजेंसी को यह आकलन हर साल करना होगा। जोखिम आकलन, नीतियों पर उसका प्रभाव और नियंत्रण की समीक्षा, समीक्षा के बाद मानक परिचालन प्रक्रिया और नीति में किये जाने वाले बदलाव के बारे में जानकारी देनी होगी। जोखिम आकलन को पूरा करने के बाद एजेंसी को मौजूदा सभी नीतियों और मानक परिचालन प्रक्रियाओं का की भी समीक्षा करनी होगी।

लॉकडाऊन का प्रभाव अप्रैल में चाय उत्पादन 54 प्रतिशत घटा

नयी दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

चाय बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार कोविड -19 महामारी को नियंत्रित करने के लिए देशव्यापी 'लॉकडाऊन' लागू किये जाने के कारण अप्रैल के महीने में भारत का चाय उत्पादन 54 प्रतिशत घटकर तीन करोड़ 90.2 लाख किलोग्राम रह गया। पिछले वर्ष इसी महीने में चाय उत्पादन आठ करोड़ 44.9 लाख किलोग्राम का हुआ था। अप्रैल में तीन करोड़ 90.2 लाख किलोग्राम के कुल चाय उत्पादन में से, लगभग तीन करोड़ 37.9 लाख किलोग्राम सीटीसी चाय की किस्म थी, जबकि 47.4 लाख किग्रा पारंपरिक चाय किस्म और 4.9 लाख किग्रा ग्रीन टी थी। अस्थायी आंकड़ों के अनुसार, असम में चाय का उत्पादन अप्रैल में घटकर एक करोड़ 32.1 लाख किलोग्राम रह गया, जो एक साल पहले चार करोड़ 49.8 लाख किलोग्राम था। पश्चिम बंगाल में अप्रैल में चाय का उत्पादन 96.4 लाख किलोग्राम का हुआ, जबकि अप्रैल 2019 में यह उत्पादन दो करोड़ 33.4 लाख किलोग्राम का हुआ था। कुल मिलाकर, उत्तर भारत में चाय का उत्पादन एक साल पहले के इसी महीने के सात करोड़ 4.7 लाख किलोग्राम से घटकर इस बार दो करोड़ 39.1 लाख किलोग्राम रह गया। हालांकि, दक्षिण भारत में उत्पादन बढ़कर एक करोड़ 51.1 लाख किलोग्राम हो गया, जो साल भर पहले एक्त अवधि के दौरान एक करोड़ 40.2 लाख किलोग्राम का हुआ था।

गन्ना किसानों के 20 हजार करोड़ चुकाने के लिए सरकार बढ़ा सकती है चीनी की कीमतें

नई दिल्ली। एजेंसी

गन्ना किसान अपने बकाया की वजह से परेशान हैं। 2019-20 का गन्ना किसानों का चीनी मिलों पर करीब 22 हजार करोड़ रुपया बकाया है। ऐसे में सरकार किसानों को राहत देने के लिए एक अहम

कदम उठाने जा रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सरकार जल्द ही चीनी का एमएसपी यानी मिनिमम सेलिंग प्राइस बढ़ा सकती है।मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सरकार चीनी की कीमतों में करीब 2 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बढ़ोतरी कर सकती है। सचिवों की एक कमेटी में चीनी की कीमत 2 रुपये बढ़ाने को मंजूरी भी मिल चुकी है। उम्मीद की जा रही है कि इस फैसले से शुगर मिलों का कैश फ्लो बढ़ जाएगा और कंपनियां आसानी से किसानों का भुगतान कर सकती हैं।

नीति आयोग ने जताई असहमति

पिछले ही हफ्ते सचिवों के एक ग्रुप ने चीनी की कीमत बढ़ाने को लेकर अपनी सहमति दे दी है। ये सुझाव देश के बड़े चीनी उत्पादक राज्यों की ओर से भी आया था। अब इस पर होने वाले फाइनल फैसले का इंतजार है। हालांकि, नीति आयोग ने इस फैसले पर अपनी असहमति जताई है।

किसानों के हित वाले कदम उठाए जाएंगे

चीनी उत्पादन वर्ष की गणना हर साल 1 अक्टूबर से अगले साल 30 सितंबर तक की जाती है। सरकारी अधिकारियों की मानें तो इस फैसले से किसानों को मदद मिले, ऐसे कदम उठाए जाएंगे।

कितना है बकाया?

स्टेट एडवाइज्ड प्राइस के अनुसार चीनी मिलों पर गन्ना किसानों का करीब 22 हजार 79 करोड़ रुपये बकाया है। वहीं केंद्र सरकार के फेयर एंड रेम्युनेरेटिव प्राइस के अनुसार बकाया 17 हजार 683 करोड़ रुपये है।

'आरोग्य संजीवनी' पॉलिसी के तहत अब कंपनियां दे सकती हैं पांच लाख से अधिक का बीमा कवर : इरडा

नयी दिल्ली। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (इरडा) ने स्वास्थ्य बीमा कंपनियों को आरोग्य संजीवनी बीमा पॉलिसी के तहत अधिकतम पांच लाख रुपये की सीमा से अधिक बीमा सुरक्षा देने की मंगलवार को अनुमति दे दी। इसके लिए उसने संशोधित नियम भी अधिसूचित कर दिए हैं। इरडा के नए दिशानिर्देशों के अनुसार साधारण और स्वास्थ्य बीमा कंपनियां आरोग्य संजीवनी पॉलिसी के लिए अब एक लाख रुपये की न्यूनतम से कम और पांच लाख रुपये की अधिकतम सीमा से ज्यादा की भी बीमा सुरक्षा दे सकेंगी। यह बीमा सुरक्षा 50,000 रुपये के गुणांकों में होगी। इसके लिए इरडा ने 'मानक व्यक्तिगत स्वास्थ्य बीमा उत्पाद' से जुड़े नियमों में संशोधन किया है। पहले इस बीमा पॉलिसी के तहत कंपनियों को न्यूनतम एक लाख रुपये और अधिकतम पांच लाख रुपये की बीमा सुरक्षा उपलब्ध कराने की अनुमति थी। यह बीमा सुरक्षा 50,000 रुपये के गुणांकों में ही उपलब्ध करायी जा सकती है। इरडा ने कहा कि कंपनियां तत्काल प्रभाव से संशोधित बीमा पॉलिसी उत्पादों की पेशकश कर सकती हैं। आरोग्य संजीवनी पॉलिसी में व्यक्ति के अस्पताल में भर्ती होने, अस्पताल में भर्ती होने और बाद के खर्चे, आयुष से होने वाला इलाज इत्यादि पर बीमा सुरक्षा मिलती है।

जून में खाद्यतेलों का आयात आठ माह में सबसे अधिक 11.62 लाख टन रहा

नयी दिल्ली। एजेंसी

देश में खाद्य तेलों का आयात जून में 11.62 लाख टन रहा है। पिछले आठ महीने में यह खाद्य तेलों का सबसे अधिक आयात हुआ है। हालांकि, इस अवधि के दौरान पाम तेल के आयात की खेप में भारी गिरावट देखी गई। तेल उद्योग के प्रमुख संगठन, साल्वेंट एक्स्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन (एसईए) ने मंगलवार को यह जानकारी दी। दुनिया में वनस्पति तेलों के प्रमुख खरीदार देश, भारत ने पिछले साल इसी महीने में 10.71 लाख टन खाद्य तेलों का आयात किया था। हालांकि, तेल वर्ष 2019-20 के दौरान नवंबर से जून अवधि की यदि बात की जाये तो इस दौरान खाद्य तेलों का आयात 15 प्रतिशत घटकर 80.51 लाख टन रह गया, जो एक साल पहले की इसी अवधि में 94.55 लाख टन रहा था। इस गिरावट का मुख्य कारण आरबीडी पामोलीन के आयात में गिरावट आना रहा। तेल वर्ष नवंबर से अक्टूबर तक चलता है।

मुंबई स्थित सॉल्वेंट एक्स्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन (एसईए) ने एक बयान में कहा, "तेल वर्ष 2019-20 के पिछले आठ महीनों में यह (जून महीने के दौरान) सर्वाधिक आयात की मात्रा है।" जून में कुल आयात में से पाम तेल का हिस्सा 5.62 लाख टन का है जबकि हल्के तेलों का हिस्सा 5.99 लाख टन का है। वास्तव में, देश में आयात होने वाले खाद्यतेल में 60 प्रतिशत से अधिक का हिस्सा पामतेल का होता है - लेकिन इस बार इसमें पिछले साल जून में हुए 6.86 लाख टन आयात के मुकाबले 18.04 प्रतिशत की गिरावट आई है। पाम तेल में से आरबीडी पामोलीन का आयात इस साल जून में भारी गिरावट के साथ 3,000 टन रह गया, जबकि साल भर पहले यह आयात 2.55 लाख टन का हुआ था। एसईए ने कहा कि इस साल आठ जनवरी से आरबीडी पामोलीन को प्रतिबंधित व्यापार श्रेणी के तहत लाने के बाद से आरबीडी पामोलीन के आयात की खेप में गिरावट जारी है। एसईए ने कहा, "वर्ष 1994 में भारत द्वारा आरबीडी पामोलीन तेल के आयात की अनुमति देने के बाद इस समय इसका सबसे कम आयात हुआ है।

पिछले साल, मलेशिया ने कम शुल्क रियायतों का लाभ उठाते हुए भारत में अत्यधिक मात्रा में आरबीडी पामोलीन की खेप भेजी थी।" हालाँकि, कच्चे पामतेल (सीपीओ) का आयात पहले के 4.21 लाख टन के मुकाबले समीक्षाधीन अवधि में कहीं अधिक यानी 5.59 लाख टन का हुआ। उक्त अवधि के दौरान ही 10,334 टन कच्चे पाम कर्नेल (गरी) तेल (सीपीकेओ) का भी आयात किया। हल्के तेलों में, सूरजमुखी तेल का आयात जून में बढ़कर 2.68 लाख टन हो गया, जो एक साल पहले के समान महीने में 1.61 लाख टन था, जबकि जून 2019 में सोयाबीन तेल का आयात 2.31 लाख टन से बढ़कर 3.31 लाख टन हो गया है। एसोसिएशन ने कहा कि लॉकडाउन की अवधि में, सूरजमुखी और सोयाबीन तेल के लिए उपभोक्ता पैक में घरेलू मांग बढ़ गयी थी, जो क्रमशः उनके आयात में 17 प्रतिशत और 13 प्रतिशत की वृद्धि से प्रकट होता है। एसईए के अनुसार, पिछले छह महीनों में मुख्य रूप से घरेलू मांग कम होने और खाद्य तेल के आयात में कमी के कारण स्टॉक में कमी आई है। एक मई को, विभिन्न बंदरगाहों पर खाद्य तेल का स्टॉक 9.15 लाख टन का था, जो एक अप्रैल को 12.30 लाख टन के स्तर से नीचे था। भारत मुख्य रूप से इंडोनेशिया और मलेशिया से पाम तेल आयात करता है, और अर्जेंटीना से सोयाबीन तेल सहित हल्के कच्चे तेल की थोड़ी मात्रा का आयात करता है। सूरजमुखी का तेल यूक्रेन और रूस से आयात किया जाता है।

शिवजी के शुभ प्रतीक

12 बातों से पहचाने जाते हैं भोलेनाथ

भगवान शिव के शुभ चिन्ह या प्रतीक बहुत ही महत्व रखते हैं। उनके प्रत्येक शुभ प्रतीकों के पीछे कुछ न कुछ रहस्य छुपा हुआ है। आंकड़े के फूल, बिल्वपत्र, जल, दूध और चंदन के अलावा भी कई चीजें उन्हें प्रिय है। आओ जानते हैं ऐसी ही 11 बातें जिनसे पहचानें जाते हैं भगवान भोलेनाथ।

भगवान शिव

1.शिवलिंग : भगवान शिव के निर्गुण और निराकार रूप का प्रतीक है शिवलिंग। यह ब्रह्म, आत्मा और ब्रह्मांड का प्रतीक भी है। वायु पुराण के अनुसार प्रलयकाल में समस्त सृष्टि जिसमें लीन हो जाती है और पुनः सृष्टिकाल में जिससे सृष्टि प्रकट होती है उसे शिवलिंग कहते हैं।

2. त्रिशूल : भगवान शिव के पास हमेशा एक त्रिशूल ही होता था। त्रिशूल 3 प्रकार के कष्टों दैनिक, दैविक, भौतिक के विनाश का सूचक भी है। इसमें 3 तरह की शक्तियां हैं- सत, रज और तम। त्रिशूल के 3 शूल सृष्टि के क्रमशः उदय, संरक्षण और लयीभूत होने का प्रतिनिधित्व करते भी हैं। शैव मतानुसार शिव इन तीनों भूमिकाओं के अधिपति हैं। यह शैव सिद्धांत के पशुपति, पशु एवं पाश का प्रतिनिधित्व करता है। माना जाता है कि यह महाकालेश्वर के 3 कालों (वर्तमान, भूत, भविष्य) का प्रतीक भी है। इसके अलावा यह स्वपिंड, ब्रह्मांड और शक्ति का परम पद से एकत्व स्थापित होने का प्रतीक है। यह वाम भाग में स्थिर इड़ा, दक्षिण भाग में स्थित पिंगला तथा मध्य देश में स्थित सुषुम्ना नाड़ियों का भी प्रतीक है।

3. रुद्राक्ष : माना जाता है कि रुद्राक्ष की उत्पत्ति शिव के आंसुओं से हुई थी। धार्मिक ग्रंथानुसार 21 मुख तक के रुद्राक्ष होने के प्रमाण हैं, परंतु वर्तमान में 14 मुखी के पश्चात सभी रुद्राक्ष अप्राप्य हैं। इसे धारण करने से सकारात्मक ऊर्जा मिलती है रक्त प्रवाह भी संतुलित रहता है।

4. त्रिपुंड तिलक : माथे पर त्रिपुंड तिलक लगाते हैं। यह तीन लंबी धारियों वाला तिलक होता है। यह त्रिलोक्य और त्रिगुण का प्रतीक है। यह सतोगुण, रजोगुण और तपोगुण का प्रतीक भी है। त्रिपुंड दो प्रकार का होता है- पहला तीन धारियों के बीच लाल रंग का एक बिंदु होता है। यह बिंदु शक्ति का प्रतीक होता है। आम इंसान को इस तरह का त्रिपुंड नहीं लगाना चाहिए। दूसरा होता है सिर्फ तीनधारियों वाला तिलक या त्रिपुंड। इससे मन एकाग्र होता है।

5. भभूत या भस्म : शिव अपने शरीर पर भस्म धारण करते हैं। भस्म जगत की निस्सारता का बोध कराती है। भस्म आकर्षण, मोह आदि से मुक्ति का प्रतीक भी है। देश में एकमात्र जगह उज्जैन के महाकाल मंदिर में शिव की भस्म आरती होती है जिसमें श्मशान की भस्म का इस्तेमाल किया जाता है। यज्ञ की भस्म में वैसे कई आयुर्वेदिक गुण होते हैं। प्रलयकाल में समस्त जगत का विनाश हो जाता है, तब केवल भस्म (राख) ही शेष रहती है। यही दशा शरीर की भी होती है।

6. डमरू : सभी हिन्दू देवी और देवताओं के पास एक न एक वाद्य यंत्र रहता है। उसी तरह भगवान के पास डमरू था, जो नाद का प्रतीक है। भगवान शिव को संगीत का जनक भी माना जाता है। उनके पहले कोई भी नाचना, गाना और बजाना नहीं जानता था। नाद अर्थात ऐसी ध्वनि, जो ब्रह्मांड में निरंतर जारी है जिसे 'ॐ' कहा जाता है। संगीत में अन्य स्वर तो आते-जाते रहते हैं, उनके बीच विद्यमान केंद्रीय स्वर नाद है। नाद से ही वाणी के चारों रूपों की उत्पत्ति मानी जाती है- 1. पर, 2. पश्यंती, 3. मध्यमा और 4. वैखरी।

7.कमंडल : कमंडल में जल होता है जो अमृत का प्रतीक है। कमंडल हर संत या योगी के पास होता है।

8. हस्ति चर्म और व्याघ्र चर्म : शिव अपनी देह पर हस्ति चर्म और व्याघ्र चर्म को धारण करते हैं। हस्ती अर्थात हाथी और व्याघ्र अर्थात शेर। हस्ती अभिमान का और व्याघ्र हिंसा का प्रतीक है अतः शिवजी ने अहंकार और हिंसा दोनों को दबा रखा है। बाघ शक्ति और सत्ता का प्रतीक है तथा शक्ति की देवी का वाहन है। भगवान शिव अक्सर इस पर बैठते हैं या इस खाल को पहनते है, जोकि यह दर्शाता है कि वह शक्ति के मालिक हैं और सभी शक्तियों से ऊपर हैं।

9. शिव कुंडल : हिन्दुओं में एक कर्ण छेदन संस्कार है। शैव, शाक्त और नाथ संप्रदाय में दीक्षा के समय कान छिदवाकर उसमें मुद्रा या कुंडल धारण करने की प्रथा है। प्राचीन मूर्तियों में प्रायः शिव और गणपति के कान में सर्प कुंडल, उमा तथा अन्य देवियों के कान में शंख अथवा पत्र कुंडल और विष्णु के कान में मकर कुंडल देखने में आता है।

दो कान के छल्ले, जिन्हें 'अलक्ष्य' (जिसका अर्थ है जो किसी भी माध्यम के द्वारा दिखाया नहीं जा सकता) और निरंजन (जिसका अर्थ है जो नश्वर आंखों से नहीं देखा जा सकता है), भगवान द्वारा पहनें गए हैं। उल्लेखनीय है कि प्रभु के बाएं कान का कुंडल महिला स्वरूप द्वारा इस्तेमाल किया गया है और उनके दाएं कान का कुंडल पुरूष स्वरूप द्वारा इस्तेमाल किया गया है। दोनों कानों में विभूषित कुंडल शिव और शक्ति (पुरुष और महिला) के रूप में सृष्टि के सिद्धांत का प्रतिनिधित्व करते हैं।

10. चन्द्रमा : शिव का एक नाम 'सोम' भी है। सोम का अर्थ चन्द्र होता है। शिव द्वारा चन्द्रमा को धारण करना मन के नियंत्रण का भी प्रतीक है। हिमालय पर्वत और समुद्र से चन्द्रमा का सीधा संबंध है। विश्व का पहला ज्योर्तिलिंग सोमनाथ में चंद्रदेव ने ही स्थापित किया था। मूलतः शिव के सभी त्योहार और पर्व चान्द्रमास पर ही आधारित होते हैं। शिवरात्रि, महाशिवरात्रि आदि शिव से जुड़े त्योहारों में चन्द्र कलाओं का महत्व है। यह अर्द्धचन्द्र शैवपंथियों और चन्द्रवंशियों के पंथ का प्रतीक चिह्न है। मध्य एशिया में यह मध्य एशियाई जाति के लोगों के ध्वज पर बना होता था। चंगेज खान के झंडे पर अर्द्धचन्द्र होता था। इस अर्धचंद्र का ध्वज पर होने का अपना ही एक अलग इतिहास है।

11. जटाएं और गंगा : शिव अंतरिक्ष के देवता हैं। उनका नाम व्योमकेश है अतः आकाश उनकी जटास्वरूप है। जटाएं वायुमंडल की प्रतीक हैं। वायु आकाश में व्याप्त रहती है। सूर्य मंडल से ऊपर परमेष्ठि मंडल है। इसके अर्थ तत्व को गंगा की संज्ञा दी गई है अतः गंगा शिव की जटा में प्रवाहित है। शिव रुद्रस्वरूप उग्र और संहारक रूप धारक भी माने गए हैं। गंगा को जटा में धारण करने के कारण ही शिव को जल चढ़ाए जाने की प्रथा शुरू हुई। जब स्वर्ग से गंगा को धरती पर उतारने का उपक्रम हुआ तो यह भी सवाल उठा कि गंगा के इस अपार वेग से धरती में विशालकाय छिद्र हो सकता है, तब गंगा पाताल में समा जाएगी। ऐसे में इस समाधान के लिए भगवान शिव ने गंगा को सर्वप्रथम अपनी जटा में विराजमान किया और फिर उसे धरती पर उतारा। गंगोत्री तीर्थ इसी घटना का गवाह है।

12. वासुकि और नंदी : वृषभ शिव का वाहन है। वे हमेशा शिव के साथ रहते हैं। वृषभ का अर्थ धर्म है। मनुस्मृति के अनुसार 'वृषो हि भगवान धर्मः'। वेद ने धर्म को 4 पैरों वाला प्राणी कहा है। उसके 4 पैर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष हैं। महादेव इस 4 पैर वाले वृषभ की सवारी करते हैं यानी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष उनके अधीन हैं। एक मान्यता के अनुसार वृषभ को नंदी भी कहा जाता है, जो शिव के एक गण हैं। नंदी ने ही धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, कामशास्त्र और मोक्षशास्त्र की रचना की थी।

उसी प्रकार शिव को नागवंशियों से घनिष्ठ लगाव था। नाग कुल के सभी लोग शिव के क्षेत्र हिमालय में ही रहते थे। कश्मीर का अनंतनाग इन नागवंशियों का गढ़ था। नाग कुल के सभी लोग शैव धर्म का पालन करते थे। भगवान शिव के नागेश्वर ज्योतिर्लिंग नाम से स्पष्ट है कि नागों के ईश्वर होने के कारण शिव का नाग या सर्प से अटूट संबंध है। भारत में नागपंचमी पर नागों की पूजा की परंपरा है। विरोधी भावों में सामंजस्य स्थापित करने वाले शिव नाग या सर्प जैसे क्रूर एवं भयानक जीव को अपने गले का हार बना लेते हैं। लिपटा हुआ नाग या सर्प जकड़ी हुई कुंडलिनी शक्ति का प्रतीक है।

युवाओं का डिजिटल हुनर निखारेगी माइक्रोसॉफ्ट, एनएसडीसी से मिलाया हाथ

बेंगलूरु। एजेंसी

दिग्गज टेक कंपनी माइक्रोसॉफ्ट (Microsoft) ने देश के युवाओं के डिजिटल स्किल को निखारने के लिए नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (NSDC) के साथ हाथ मिलाया है। इसके तहत अगले एक साल में देश में एक लाख से अधिक युवाओं को डिजिटली सक्षम बनाया जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट और एनएसडीसी की साझेदारी का मकसद भारत को स्किल्ड नेशन में बदलना है। इसके तहत माइक्रोसॉफ्ट एनएसडीसी के ईस्किल इंडिया पोर्टल के साथ समन्वय करेगी ताकि नई पीढ़ी को डिजिटल स्किल की बारीकियां सिखाई जा सकें। देश को डिजिटल इकनॉमी बनाने के लिए यह बहुत जरूरी है।

इस साझेदारी के तहत माइक्रोसॉफ्ट के लर्निंग रिसोर्स सेंटर माइक्रोसॉफ्ट लर्न को ईस्किल इंडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ जोड़ा जाएगा। ताकि युवाओं को आज की डिजिटल इकनॉमी की बारीकियों से रूबरू कराया जा सके। इसके तहत इन युवाओं के एंट्री लेवल से लेकर एआई और क्लाउड कम्प्यूटिंग जैसे एडवांस लेवल की क्रिटिकल तकनीक से अवगत कराया जाएगा। एनएसडीसी के साथ पार्टनरशिप माइक्रोसॉफ्ट की ग्लोबल स्किलिंग इनिशिएटिव का विस्तार है। इसके तहत कंपनी पूरी दुनिया में 2.5 करोड़ लोगों को नए डिजिटल स्किल सिखा रही है जिनकी कोविड-19 इकनॉमी में जरूरत है।

डिजिटल इकनॉमी पर जोर

माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के प्रेजिडेंट अनंत माहेश्वरी ने कहा, 'देश में डिजिटल बदलाव से हर इंडस्ट्री में टेक से जुड़े रोजगार की मांग बढ़ रही है और इसके साथ डिजिटल स्किल्स की जरूरत भी बढ़ रही है। हम डिजिटल स्किल्स इकोसिस्टम बना रहे हैं जो भविष्य के लिए भारत के वर्कफोर्स को तैयार करेगी। एनएसडीसी के साथ हमारी साझेदारी इस दिशा में एक अहम कदम है। इससे युवाओं को डिजिटल इकनॉमी के लिए अपने हुनर को मांजने का मौका मिलेगा।'

एनएसडीसी के सीईओ और एमडी मनीष कुमार ने कहा, 'इस करार का मकसद युवाओं को तेजी से उभर डिजिटल इकनॉमी के लिए तैयार करना है। इसमें नए जमाने की एडवांस स्किल पर जोर रहेगा और इससे हमारी अर्थव्यवस्था की बढ़ती मांगों को पूरा किया जा सकेगा।'

भारतीय बाजार में सफलता के लिए फिनलैंड के नाम, सुरक्षा पर ध्यान दे रही है नोकिया

नयी दिल्ली। नोकिया ब्रांड के मोबाइल फोन बेचने वाली कंपनी एचएमडी ग्लोबल भारतीय बाजार में सफलता के लिए फिनलैंड के नाम और सुरक्षित उत्पादों पर ध्यान दे रही है। भारतीय बाजार में एचएमडी को शाओमी, सैमसंग और अन्य कंपनियों से प्रतिस्पर्धा है। कंपनी स्मार्टफोन और फीचर फोन दोनों बेचती है। कंपनी का मानना है कि भारतीय बाजार में क्षमता है और यहां बिक्री के आंकड़े कोविड-19 से पूर्व के स्तर पर पहुंच रहे हैं। एचएमडी ग्लोबल के उपाध्यक्ष सन्मीत कोचर ने से कहा, "हम एकमात्र यूरोपीय मोबाइल फोन ब्रांड हैं। हमारे परिचालन का मूल विचार यह है कि मोबाइल प्रौद्योगिकी दुनियाभर में लोगों के जीवन में सुधार ला सकती है। हमारा विश्वास है कि प्रत्येक नोकिया फोन के निर्माण का मुख्य आधार सुरक्षा, विश्वसनीयता और उनका टिकाऊ होना है।" कंपनी के भारत सहित दुनिया में पांच संयंत्र हैं। सिर्फ नोकिया 9 प्योरव्यू और नाकिया 8 सिरिको को छोड़कर नोकिया के सभी फोन का विनिर्माण गई मूल डिजाइन विनिर्माताओं (ओडीएम) के साथ भागीदारी में स्थानीय स्तर पर होता है। कोचर ने कहा कि कंपनी अपने पोर्टफोलियो के सभी फोन पर मासिक सुरक्षा अपडेट उपलब्ध कराने को प्रतिबद्ध है। इसमें उपकरण की कीमत से कोई लेना-देना नहीं है।

गंगा पुनरोद्धार के लिए 40 करोड़ डॉलर की ऋण सहायता देगा विश्वबैंक

नयी दिल्ली। एजेंसी

विश्वबैंक नमामि गंगे कार्यक्रम को समर्थन बढ़ाने को 40 करोड़ डॉलर (3,023.10 करोड़ रुपये) की ऋण सहायता देगा। यह गंगा नदी के पुनरोद्धार का कार्यक्रम है। विश्वबैंक ने मंगलवार को कहा कि दूसरी राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन परियोजना (एसएनजीआरबीपी) से नदी का प्रदूषण कम करने और नदी बेसिन का प्रबंधन मजबूत करने में मदद मिलेगी। विश्वबैंक ने बयान में कहा कि इस 40 करोड़ डॉलर में से 38.1 करोड़ डॉलर 2,879 करोड़ रुपये) ऋण के रूप में और 1.9 करोड़ डॉलर (143 करोड़ रुपये) विश्वबैंक गारंटी के रूप में होंगे। इस 38.1 करोड़ डॉलर के ऋण करार पर भारत सरकार की ओर से आर्थिक मामलों के विभाग में अतिरिक्त सचिव समीर कुमार खरे और विश्वबैंक के भारत में कार्यवाहक निदेशक कैसर खान ने हस्ताक्षर किए।" गारंटी वाले पक्ष पर बात में व्यवस्था की जाएगी। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने कहा कि इसमें से 15 करोड़ डॉलर या 1,134 करोड़ रुपये का इस्तेमाल तीन नई हाइब्रिड एन्यूइटी मोड परियोजनाओं में किया जाएगा। यह राशि आगरा, मेरठ सहारनपुर में गंगा की सहायक नदियों (यमुना और काली) पर खर्च की जाएगी। इसके अलावा 16 करोड़ डॉलर की राशि बक्सर, मुंगेर, बेगूसराय की मौजूदा डिजाइन, निर्माण, परिचालन और स्थानांतरण (डीबीओटी) परियोजनाओं तथा दीघा, कंकड़बाग-पटना तथा हावड़ा, बैली और बड़ानगर-पश्चिम बंगाल की हाइब्रिड एन्यूइटी मोड परियोजनाओं पर खर्च की जाएगी। विश्वबैंक गंगा के पुनरोद्धार के सरकार के प्रयासों में 2011 से समर्थन कर रहा है।

माईलैब की कोविड-19, अन्य जांच स्वचालित तरीके से पूरा करने वाली मशीन पेश, बुकिंग 13 जुलाई से

नयी दिल्ली। एजेंसी

देश की पहली स्वदेशी कोविड-19 जांच किट बनाने की अनुमति प्राप्त करने वाली पुणे की माइलैब डिस्कवरी सॉल्युशंस ने प्रयोगशाला में की जाने वाली आणविक निदान जांचों को स्वचालित तरीके से पूरा करने वाली मशीन 'कॉम्पैक्ट एक्सएल' पेश की है। कंपनी का दावा है कि यह मशीन आरटी-पीसीआर किट से की जाने वाली कोविड-19 जांच के परिणाम देने में भी काम आती है। कंपनी ने मंगलवार को एक बयान में कहा कि वह 13 जुलाई से इस मशीन के ऑर्डर लेना शुरू कर देगी। हालांकि अभी कंपनी ने इसकी आपूर्ति करने की तारीख और कीमत का खुलासा नहीं किया है। गौरतलब है कि इससे पहले कंपनी को मार्च में केंद्रीय दवा मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) से अपनी कोविड-19 जांच किट के वाणिज्यिक उत्पादन की मंजूरी मिली थी। कंपनी की किट भारत निर्मित पहली ऐसी ऐसी किसी किट थी जिसे सरकार की मंजूरी मिली। बयान के मुताबिक 'कॉम्पैक्ट एक्सएल' से मात्र 43 फुट की जगह में मेज के ऊपर रखकर भी काम लिया जा सकता है। यह मशीन जांच के नमूनों को संभालने से लेकर परीक्षण तक की कई मानवीय प्रयोगशाला प्रक्रियाओं को खुद से करने में सक्षम है। यह एक बार में कई तरह के 32 नमूनों का परीक्षण कर सकती है। नेटवर्क से जोड़ने के बाद नमूनों की संख्या को 32 से आगे भी बढ़ाया जा सकता है। यह कोविड-19 के संक्रमण का पता लगाने वाली आरटी-पीसीआर किट से लिए गए नमूनों का भी परीक्षण कर सकती है। कंपनी का दावा है कि इससे जांच पूरी करने के लिए प्रयोगशाला में काम करने वाले 3 से 4 विशेषज्ञों के बजाय बस एक विशेषज्ञ की जरूरत होगी। यह प्रयोगशाला के 700 वर्गफुट के साफ कमरे की जगह लेने में सक्षम है। यह जांच प्रयोगशालाओं की लागत को कम करेगी। यह मशीन प्लाज्मा, ऊतक और बलगम जैसे नमूनों की जांच कर सकती है। यह आरएनए और डीएनए आधारित विभिन्न तरह की जांच करने में सक्षम है। यह प्रिंटर में इस्तेमाल होने वाली कार्टेज की तरह ही कार्टेज प्रौद्योगिकी से चलने वाली मशीन है। माईलैब के प्रबंध निदेशक हसमुख रावल ने कहा कि उन्नत जांच प्रक्रियाओं में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए यह हमारा अब तक का सबसे महत्वाकांक्षी उत्पाद है। कंपनी की इस पेशकश के मौके पर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के चेयरमैन साइरस पूनावाला और एपी ग्लोबल के चेयरमैन अभिजीत पवार मौजूद रहे।गौरतलब है कि कोविड-19 जांच किट का उत्पादन तेज करने के लिए माईलैब ने अप्रैल में सीरम इंस्टीट्यूट और एपी ग्लोबल के साथ गठजोड़ करने की घोषणा की थी।

Maruti की नई पहल!

Rail से भेजी 6 लाख से ज्यादा कारें, बचाया 10 करोड़ लीटर पेट्रोल

नई दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

भारत की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया (Maruti Suzuki) एमएसआई ने पिछले छह साल में भारतीय रेलवे से 6.7 लाख कारें देश के विभिन्न हिस्सों में बिक्री के लिए भेजी। कंपनी ने एक बयान में बताया कि इस दौरान इसमें 18 फीसदी से अधिक की सीएजीआर दर्ज की गई। कंपनी ने मार्च 2014 में डबल डेकर फ्लेक्सी-डेक रैक के जरिए अपनी कारों की पहली खेप भेजी थी। मारुति का कहना है कि अपनी कारों को देश के विभिन्न हिस्सों में भेजने के लिए रेलवे के इस्तेमाल से उसे करीब 3000 मीट्रिक टन कार्बन डाई ऑक्साइड के उत्सर्जन को कम करने में मदद मिली है. इससे करीब 10 करोड़ लीटर जीवाश्म ईंधन की बचत हुई।

अगर इन कारों को ट्रकों के जरिए भेजा तो लगाने पड़ते एक लाख से अधिक चक्कर

अगर इन कारों को ट्रकों के जरिए भेजा जाता तो इसके लिए ट्रकों को राष्ट्रीय राजमार्गों पर एक लाख से अधिक चक्कर लगाने पड़ते। पिछले वित्त वर्ष के दौरान 1.78 लाख से अधिक कारों को रेलवे के जरिए भेजा गया जो उससे पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 15 फीसदी अधिक है. यह साल में कंपनी के कुल बिक्री का 12 फीसदी है। कारों की ढुलाई में रेलवे की अहमियत का जिक्र करते हुए एमएसआई के एमडी और सीईओ केनिची आयुकावा ने कहा कि बढ़ती बिक्री के मद्देनजर हमारी टीम को लार्ज स्केल लॉजिस्टिक्स की जरूरत महसूस हुई। हमें लगा कि न केवल विस्तार के लिए बल्कि खतरा कम करने के लिए भी हमें रोड मोड लॉजिस्टिक्स के इतर विकल्प देखने चाहिए।

हर रैक में 318 कारे आ जाती हैं

कंपनी ने सिंगल डेक वैगन से शुरुआत की जिसमें 125 कारों की ढुलाई की जा सकती थी। फिर कंपनी ने डबल-डेकर रैक्स में शिफ्ट किया जिनमें 265 कारों को ले जाया जा सकता है। अब तक इनके जरिए 1.4 लाख से अधिक कारों को भेजा जा चुका है। कंपनी 27 रैक्स का इस्तेमाल कर रही है जो करीब 95 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकते हैं। हर रैक में 318 कारों को ले जाया जा सकता है।

देश की पहली ऑटो कंपनी जिसे ऑटोमोबाइल फ्रेट ट्रेन ऑपरेटर का लाइसेंस मिला

एमएसआई ने दावा किया कि वह देश की पहली ऑटो कंपनी है जिसने ऑटोमोबाइल फ्रेट ट्रेन ऑपरेटर (AFTO) का लाइसेंस मिला है। इससे प्राइवेट कंपनियां इंडियन रेलवे के नेटवर्क पर हाई स्पीड, हाई कैपेसिटी ऑटो वैगन रैक्स ऑपरेट कर सकते हैं। अभी कंपनी 5 लोडिंग टर्मिनल और 13 डेस्टिनेशन टर्मिनल का इस्तेमाल करती है। अगरतला के रेल नक्शे से जुड़ने से अब रेल मोड की पहुंच पूर्वोत्तर तक हो गई है। कंपनी का कहना है कि इससे पूर्वोत्तर के राज्यों तक कारों को पहुंचने में अब आधा समय लगेगा।

कंपनियों की Hiring Activities में आई तेजी

जून महीने में मई की तुलना में आया 33 फीसद का उछाल: रिपोर्ट

नई दिल्ली। एजेंसी

जून महीने में हायरिंग एक्टिविटीज में मई की तुलना में तेजी आई है। कोरोना वायरस संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए लागू लॉकडाउन में ढील के चलते हायरिंग एक्टिविटीज जून महीने में बढ़ी हैं। हालांकि, सालाना आधार पर देखें, तो हायरिंग एक्टिविटीज अभी भी निराशाजनक ही है। एक रिपोर्ट में बुधवार को यह जानकारी दी गई है। जून महीने की नौकरी जॉबस्पीक इंडेक्स पिछले महीने की तुलना में 33 फीसद के सुधार के साथ 1,208 पर रही है। मई महीने में यह 910 पर थी। हालांकि, सालाना आधार पर हायरिंग एक्टिविटीज में अभी भी 44 फीसद की गिरावट है। नौकरी जॉबस्पीक एक मासिक सूचकांक है, जो नौकरी डॉट कॉम पर लिस्टेड होने वाली नौकरियों के आधार पर हायरिंग एक्टिविटीज की गणना करता है। रिपोर्ट के अनुसार, कोरोना वायरस संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन के कारण हॉस्पिटैलिटी, रिटेल और ऑटो सेक्टर में हायरिंग पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा था। अब लॉकडाउन में ढील के बाद इन सेक्टर्स में हायरिंग एक्टिविटीज में सुधार हुआ है। रिपोर्ट में आगे बताया गया, 'जून में सरकार द्वारा अनलॉक 1.0 लागू करने के साथ हमें इन सेक्टर्स में हायरिंग गतिविधियां फिर से होती दिखी हैं। जून महीने में हॉस्पिटैलिटी सेक्टर की हायरिंग गतिविधियों में मासिक आधार पर 107 फीसद की तेजी आई है। वहीं, खुदरा व ऑटो क्षेत्र में से प्रत्येक में 77 फीसद की बढ़त हुई है।' नौकरी डॉट कॉम के मुख्य व्यापार अधिकारी पवन गोयल ने कहा, 'यह उत्साहजनक है कि भारत में अनलॉक 1.0 की घोषणा के परिणामस्वरूप हायरिंग गतिविधियों में मासिक आधार पर तेजी देखने को मिली है।' गोयल ने आगे कहा, 'हालांकि, सालना आधार पर देखें, तो हायरिंग गतिविधियां अभी भी प्रभावित हैं और इसमें 44 फीसद की गिरावट है। वहीं, आईटी, बीपीओ/आईटीईएस, एफएमसीजी और अकाउंटिंग जैसे प्रमुख उद्योगों में जून महीने में पिछले दो महीनों के मुकाबले हायरिंग में महत्वपूर्ण तेजी आई है।' उन्होंने आगे कहा, 'हमें आशा है कि आने वाले महीनों में हायरिंग एक्टिविटीज में तेज उछाल देखने को मिलेगा।' रिपोर्ट में बताया गया कि जून महीने में मासिक आधार पर हायरिंग में एजुकेशन/टीचिंग की कार्यात्मक भूमिकाओं में 49 फीसद, फार्मा/बायोटेक में 36 फीसद और सेल्स/बिजनेस डेवलपमेंट में 33 फीसद की तेजी देखी गई है। रिपोर्ट में बताया गया कि जून महीने में मासिक आधार पर हायरिंग में एजुकेशन/टीचिंग की कार्यात्मक भूमिकाओं में 49 फीसद, फार्मा/बायोटेक में 36 फीसद और सेल्स/बिजनेस डेवलपमेंट में 33 फीसद की तेजी देखी गई है।

वॉट्सऐप ने भारत में अपना ब्रांड अभियान 'इट्स बिटवीन यू' किया शुरू, जीतना चाहता है सबको दिल और भरोसा

नई दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

वॉट्सऐप ने भारत में अपना ब्रांड अभियान 'इट्स बिटवीन यू' शुरू किया है। कंपनी ने कहा है कि इस अभियान के जरिये वह बताएगी कि भारतीय एक-दूसरे के संपर्क में रहने के लिए किस तरह सुरक्षित तरीके से फेसबुक के स्वामित्व वाले मंच का इस्तेमाल करते हैं। इस अभियान के लिए वॉट्सऐप ने बॉलीवुड निदेशक गौरी शिंदे और विज्ञापन एजेंसी बीबीडीओ इंडिया की सेवाएं ली हैं। इसके तहत वॉट्सऐप दो विज्ञापन बनाएगी जिसमें दिखाया जाएगा कि कैसे उसके संदेश भेजने, वीडियो कॉल करने या वॉयस संदेश भेजने के फीचर्स लोगों को एक-दूसरे से जोड़ते हैं। भारत में वॉट्सऐप के प्रयोगकर्ताओं की संख्या 40 करोड़ से अधिक है और यह उसके सबसे बड़े बाजारों में से है।

बताई जाएंगी सच्ची कहानियां

फेसबुक इंडिया के निदेशक (विपणन) अविनाश पंत ने कहा, 'इस अभियान के जरिये वे सच्ची कहानियां बताई जाएंगी कि कैसे भारतीय रोजाना अपने नजदीकी लोगों के साथ वॉट्सऐप के जरिये संपर्क में रहते हैं।' पंत ने कहा, 'वॉट्सऐप उन लोगों के लिए जीवनरेखा की तरह है जो अपने दोस्तों-परिवार से काफी दूर हैं। यह उनके साथ संपर्क में रहने का एक बेहतरीन माध्यम है।'

10 हफ्ते तक चलेगा ये अभियान

उन्होंने बताया कि इनमें से एक विज्ञापन बुजुर्ग महिला और उसकी देखभाल करने वाले से संबंधित है। दूसरा विज्ञापन दो बहनों के बारे में है। वॉट्सऐप ने ब्राजील में इसी साल इस तरह का अभियान चलाया था। पंत ने बताया कि देशभर में यह अभियान 10 सप्ताह तक कई राष्ट्रीय और क्षेत्रीय टेलीविजन चैनलों और डिजिटल मंचों पर चलाया जाएगा।

10 हजार कृषक उत्पादक संगठनों की स्थापना से ग्रामीण क्षेत्रों में होगा व्यापक बदलाव: तोमर

नयी दिल्ली। एजेंसी

कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने को कहा कि 10,000 किसानों उत्पादक संगठनों (एफपीओ) का गठन करके ग्रामीण क्षेत्र का रूपांतरण किया जाएगा, जो न केवल कृषि क्षेत्र कक्की प्रगति में मदद करेगा, बल्कि विकास के नए रास्ते भी बनाएगा। तोमर ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लगु उद्योग भारती और सहकार भारती की बैठक को संबोधित करते हुए कहा, 'देश में 86 प्रतिशत किसान छोटे और सीमांत किसान हैं, जो इन एफपीओ के माध्यम से न केवल ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करेंगे जिससे न केवल कृषि प्रगति हासिल करने में मदद मिलेगी बल्कि इससे देश के विकास के नए रास्ते भी बनेंगे।' ।

इस बैठक में कृषि राज्य मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला और कैलाश चौधरी तथा केंद्रीय जल संसाधन राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी उपस्थित थे। एक सरकारी बयान में तोमर के हवाले से कहा गया है कि उन्होंने सम्मेलन में कहा कि शुरुआत में, मैदानी भागों में एफपीओ में सदस्यों की न्यूनतम संख्या 300 और उत्तर-पूर्व और पहाड़ी क्षेत्रों में 100 होगी। उन्होंने कहा कि छोटे, सीमांत और भूमिहीन किसानों के लाभ के लिए बनाये जा रहे एफपीओ को इस तरह से प्रबंधित किया जाएगा कि इन किसानों को उनकी फसलों के लिए तकनीकी आदानों की प्राप्ति हो सके, उन्हें वित्त और बेहतर बाजारों तक पहुंच मिलने के साथ साथ अपनी ऊपज के लिए बेहतर कीमत मिल सके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा परिकल्पित वर्ष 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने के लक्ष्य को पूरा किया जा सके।

तोमर ने कहा कि एफपीओ उत्पादन और विपणन की लागत को कम करने में मदद करेगा तथा कृषि और बागवानी क्षेत्रों में उत्पादन को बढ़ाने में भी मदद करेगा और इससे रोजगार के अवसर को भी बढ़ाने में मदद मिलेगी। खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए, मंत्री ने कहा कि बजट 2020-21 में, 'एक जिला - एक उत्पाद' (वन डिस्ट्रिक्ट - वन प्रोडक्ट) योजना के माध्यम से बागवानी उत्पादों के लिए क्लस्टर दृष्टिकोण अपनाने का प्रस्ताव है, ताकि मूल्य संवर्धन, विपणन और निर्यात को बढ़ावा दिया जा सके। यह एक केंद्रीय योजना है, जिसका कुल बजट 6,865 करोड़ रुपये है। सभी एफपीओ को पांच साल के लिए पेशेवर सहायता और मदद प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि एफपीओ का लगभग 15 प्रतिशत आकांक्षात्मक जिलों में गठन किया जाना है, और अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों में इसे प्राथमिकता के आधार पर गठित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह एक उत्पाद आधारित क्लस्टर योजना है। एफपीओ जैविक और प्राकृतिक खेती को भी बढ़ावा देगा।

आत्म-निर्भरता हासिल करने के लिए बड़े आयात वाले 15 उत्पादों पर ध्यान केंद्रित करे भारत : एसोचैम

नयी दिल्ली। उद्योग मंडल एसोचैम मानना है कि आत्म-निर्भर भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए देश को 15 बड़े आयात वाले उत्पादों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और देश में उनके उत्पादन की क्षमता बढ़ानी चाहिए। उद्योग मंडल ने ऐसे 15 उत्पादों को चिह्नित करते हुए कहा है कि इनका घरेलू उत्पादन बढ़ाकर हम दो-तीन साल में आत्म-निर्भर भारत के लक्ष्य को पा सकते हैं। इन उत्पादों में इलेक्ट्रॉनिक्स, कोयला, लौह-चादर, अलौह धातु, वनस्पति तेल आदि शामिल हैं। यह विश्लेषण ताजा आंकड़ों पर आधारित है। आंकड़ों से पता चलता है कि गैर-तेल आयात खंड में इलेक्ट्रॉनिक्स सामान का हिस्सा सबसे अधिक है। देश के आंशिक लॉकडाउन के बावजूद मईं, 2020 में भारत ने 2.8 अरब डॉलर मूल्य के इलेक्ट्रॉनिक्स सामान का आयात किया। एसोचैम ने एक नोट में कहा, "उद्योग के सामान्य परिचालन के दिनों यह आयात एक महीने करीब पांच अरब डॉलर रहता है। इस पर एक बड़ी विदेशी मुद्रा खर्च होती है।" एसोचैम के महासचिव दीपक सूद ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की हालिया उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना और चैंपियनों को प्रोत्साहन पासा पलटने वाला साबित हो सकता है। इस प्रयास में घरेलू ओर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश दोनो को प्रोत्साहन देने की जरूरत है। उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना (पीएलआई) बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित है। इसके तहत घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने और मोबाइल फोन उत्पादन, विशेष इलेक्ट्रॉनिक कलपुर्जों जिसमें असेंबली, परीक्षण, मार्किंग और पैकेजिंग (एटीएमपी) इकाइयां शामिल हैं, में बड़ा निवेश आकर्षित करने के लिए प्रोत्साहन दिया जाता है। उद्योग ने गैर-तेल ओर गैर-सोना आयात से अलग ऐसे उत्पादों की पहचान की है जिनपर अच्छी-खासी विदेशी मुद्रा खर्च होती है। इन उत्पादों में इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान, इलेक्ट्रिकल और गैर-इलेक्ट्रिकल मशीनरी, लौह एवं इस्पात, जैविक और अजैविक रसायन, कोयला-कोक और ब्रिकेट, अलौह धातु, परिवहन उपकरण और फार्मास्युटिकल्स शामिल है। इस सूची में वनस्पति तेल, उर्वरक, डाइंग, टैनिंग और कलरिंग का सामान, पेशेवर उपकरण और ऑप्टिकल्स, फल और सब्जियां भी शामिल हैं।

स्वामी/मुद्रक/प्रकाशक सचिन बंसल द्वारा अपनी दुनिया प्रिंटर्स, 13, प्रेस काम्पलेक्स, ए.बी. रोड, इंदौर से मुद्रित एवं 18, सेक्टर-डी-2, सांवेर रोड, इंडस्ट्रीयल एरिया, जिला इंदौर (म.प्र.) से प्रकाशित। संपादक- सचिन बंसल

सूचना/चेतावनी- इंडियन प्लास्ट टाइम्स अखबार के पूरे या किसी भी भाग का उपयोग, पुन: प्रकाशन, या व्यावसायिक उपयोग बिना संपादक की अनुमति के करना वर्जित है। अखबार में छपे लेख या विज्ञापन का उद्देश्य सूचना और प्रस्तुतिकरण मात्र है। अखबार किसी भी प्रकार के लेख या विज्ञापन से किसी भी संस्थान की सिफारिश या समर्थन नहीं करता है। पाठक किसी भी व्यावसायिक गतिविधि के लिए स्वविवेक से निर्णय करें। किसी भी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र इंदौर, मप्र रहेगा।